



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 507]
No. 507]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 1986/कार्तिक 13, 1908
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 1986/KARTIKA 13, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

विधि और न्याय संज्ञासंग

(न्याय विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1986

भा.का.नि. 1175(अ).—उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) की धारा 24 के साथ पठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1986 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1956 में,—

(i) नियम 2 में, दूसरे परन्तुक के लिए निम्नलिखित उपबंध प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु आगे शर्त यह है कि डाक्टरी इलाज और अस्पतालों में आश्रम की सुविधाओं के संबंध में :—

(क) दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की छोड़कर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के मामले में, वे नियम और उपबंध लागू होंगे जो ऐसे राज्य विशेष के कैबिनेट मंत्री की प्रयोजनीय हो जहाँ उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित हो ;

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की छोड़कर न्यायाधीशों के मामले में वे नियम तथा उपबंध लागू होंगे जो किसी उप-मंत्री पर लागू होंगे ;

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के मामले में, वे नियम और उपबंध लागू होंगे जो किसी केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री पर लागू होंगे ;

(ii) नियम 2-क में, स्पष्टीकरण में पैराग्राफ (ख) में “उपभोग किए गए पानी तथा बिजली” शब्दों के बाद और “जिनका बहन किया जाएगा” शब्दों से पहले, निम्नलिखित शब्दों और कोष्ठकों को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :—
“(बारह हजार रुपए प्रति वर्ष से अधिक राशि)” ;

(iii) नियम 2-ख में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) सरकारी आवास के आबंधन के मामले में—

- (i) दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उस राज्य के कैबिनेट मंत्री को उपलब्ध वेतनमान से पांच हजार रुपए अधिक, जिस राज्य में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है ;
- (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्राबंठित सरकारी निवास के मामले में, उसी वेतनमान में जो केन्द्रीय कैबिनेट मंत्रियों को उपलब्ध है ।
- (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राबंठित सरकारी निवास के मामले में, "उसी वेतनमान में जो उस राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को उपलब्ध है जहाँ उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थित है";
- (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय या पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राबंठित सरकारी निवास के मामले में, उन्हीं वेतनमानों पर जो केन्द्रीय उप-मंत्रियों को उपलब्ध है ;

- (iv) नियम 2ग के बाद, निम्नलिखित नियम शामिल किया जाएगा, अर्थात् :—

"2घ-पेंशन की बकाया राशि का भुगतान कोई भी न्यायाधीश, पेंशन की बकाया राशि का भुगतान (नामांकन) नियम, 1983 के उपबंधों के अनुसरण में उसको मिलने वाली पेंशन की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है" ।

[सं. 24/20/86-न्याय]

फुट नोट :—मुख्य नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3 के पृष्ठ 106 में अधिसूचना सं. एम. आर. आ. सं. 224 दिनांक 24 जनवरी, 1956 को प्रकाशित हुए हैं ।

बाद के संशोधन :—

1. एम.आर.आ. 707, दिनांक 28-2-1957
2. सा.का.नि. 197, दिनांक 13-3-1970
3. सा.का.नि. 336(अ), दिनांक 11-7-1972
4. सा.का.नि. 562, दिनांक 21-4-1979
5. सा.का.नि. 1015, दिनांक 21-7-1979

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 4th November, 1986

NOTIFICATIONS

G.S.R. 1175(E).—In exercise of the powers conferred by Section 23 read with Section 24 of the High Courts Judges (Conditions of service) Act, 1954 (28 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the High Courts Judges Rules, 1956, namely :—

1. (i) These rules may be called the High Court Judges (Amendment) Rules, 1986.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the High Court Judges Rules, 1956,—

- (i) in rule 2, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided further that, in respect of facilities for medical treatment and accommodation in hospitals,—

- (a) in the case of Judges of the High Courts other than the Delhi High Court and the Punjab and Haryana High Court, the rules and provisions as applicable to a Cabinet Minister of the State Government in which the principal seat of the High Court is situated, shall apply ;

- (b) in the case of Judges, other than the Chief Justices, of the Delhi High Court and the Punjab and Haryana High Court, the rules and provisions as applicable to a Union Deputy Minister shall apply ;

- (c) in the case of the Chief Justices of the Delhi High Court and the Punjab and Haryana High Court, the rules and provisions as applicable to a Union Cabinet Minister shall apply ;

- (ii) in rule 2A, in the Explanation, in paragraph (b), after the words "water and electricity consumed" and before the words "which shall be borne", the following brackets and the words shall be inserted, namely :

"(in excess of rupees twelve thousand per annum)" ;

- (iii) in rule 2B, clauses (a) and (b) shall be substituted by the following, namely :—

"(a) in the case of an official residence allotted to—

- (i) the Chief Justice of a High Court, other than the Delhi High Court and the Punjab and Haryana High Court, rupees five thousand more than the scale provided to a Cabinet Minister of the State Government in which the principal seat of the High Court is situated ;

- (b) the Chief Justice of the Delhi High Court or Punjab and Haryana High Court, on the same scales as provided for the Union Cabinet Ministers.

- (c) a Judge of a High Court, other than the Delhi High Court and the Punjab and Haryana High Court, "on the same scales as provided to the Cabinet Ministers of the State Government in which the principal seat of the High Court is situated" ;

- (d) a Judge of the Delhi High Court or the Punjab and Haryana High Court, on the same scales as provided for the Union Deputy Ministers."

(iv) after rule 2C, the following rule shall be inserted, namely :—

“2D—A Judge of a High Court may nominate any other person to receive the arrears of pension payable to him in accordance with the provision of the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983”.

[No. 24/20/86-Jus.]

J. S. BADHAN, Jt. Secy.

Foot Note.—Principal Rules published by Notification No. S.R.O. 224, dated 24th January, 1956, Gazette of India, 1956, Part II Section 3, page 106. Subsequently amended by :—

1. S.R.O. 707 dated 28-2-1957.
2. G.S.R. 497 dated 13-3-1970.
3. G.S.R. 336(E) dated 11-7-1972.
4. G.S.R. 562 dated 21-4-1979.
5. G.S.R. 1015 dated 21-7-1979.

सा.का.नि. 1176(अ).—उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (मेवा शर्ते) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम 1959 में आगे श्री गरीधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1986 कहलायेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रयुक्त होंगे।

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 में—

- (i) नियम 3 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा; अर्थात्—
“3क—पेंशन की बकाया राशि का भुगतान; कोई भी न्यायाधीश, पेंशन की बकाया भुगतान (नामांकन) नियम 1983 के उपबन्धों के अनुसरण में उसको मिलने वाली पेंशन की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है”;
- (ii) नियम 4 के नीचे स्पष्टीकरण में कोष्ठक तथा शब्द “(दो हजार चार सौ रुपये प्रतिवर्ष से अधिक राशि)” के स्थान पर कोष्ठक तथा शब्द “बारह हजार रुपये प्रतिवर्ष से अधिक राशि)” रखे जायेंगे।

[एफ सं. 24/20/86-न्याय]

जे. एस. बधन, संयुक्त सचिव

फुट नोट: मुख्य नियम भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3(i) पृष्ठ 1161 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 935 दिनांक 4 अगस्त, 1959 को प्रकाशित हुए हैं।

बाद के संशोधन :—

1. अधिसूचना सं. 1/34/74 न्याय (1) दिनांक 18-12-74
2. सा.का.नि. 634 दिनांक 22-4-1976
3. सा.का.नि. 854 दिनांक 1-8-1980

G.S.R. 1176(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Supreme Court Judges Rules, 1959,—

(i) after rule 3, the following rule shall be inserted, namely :—

“3A—Payment of arrears of pension—
A Judge may nominate any other person to receive the arrears of pension payable to him in accordance with the provisions of the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983.”

(ii) in the Explanation below rule 4, for the brackets and words “(in excess of rupees two thousand and four hundred per annum)”, the brackets and words “(in excess of rupees twelve thousand per annum)”, shall be substituted.

[F. No. 24/20/86-Jus.]

J. S. BADHAN, Jt. Secy.

Foot Note.—Principal Rules published vide Notification No. G.S.R. 935 dated the 4th August, 1959 Gazette of India, Part II, Section 3(i) page 1161.

Subsequently amended by :—

1. Notification No. 1/34/74-Jus. (i) dated 18-12-1974.
2. G.S.R. 634 dated 22-4-1976.
3. G.S.R. 854 dated 1-8-1980.

